वर्ष	सेवा प्रभारों की राशि	विकास कार्यों पर खर्च की गई धनराशि
1993-94	50,00,000/- रुपए	46,60,520/- रुपए
1994-95	88,61,477/- रुपए	21,83,191/- रुपए
1995-96	3,98,62,363/- रुपए	94,89,145/- रुपए

विवरण

पिछले 5 वर्षों के दौरान छावनी क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत और वित्तपोषित योजनाओं के विवरण

	योजना/कार्यों के नाम	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96 (लाख रुपए में)
1.	जलापूर्ति	50.00	2.10	90.00	2.64	8.50
2.	शुष्क शौचालयों को पानी युक्त शौचालयों में बदलना	—	15.00	—	—	132.27
3.	सड़कों की मरम्मत	7.92	4.00	2.00	—	16.47
4.	भवनों की मरम्मत	3.90	6.42	—	—	—
5.	विविध प्रकार के विकास	2.18	2.30	—	—	7.21
	योग:	64.00	29.82	92.00	2.64	164.45

राज्य के आधार पर नई रेजिमेंटों का गठन

2610. **श्री नागमणि:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार जाति के आधार पर गठित रेजिमेंटों को समाप्त करके उन्हें राज्य के आधार पर गठित करने पर विचार कर रही है क्योंकि रक्षा मामलों में जाति के आधार पर गठित रेजिमेंटों से भेदभाव किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन० वी० एन० सोमू): (क) से (ग) स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले कुछ रेजिमेंटों के नाम उन प्रमुख वर्ग/राज्य/क्षेत्र के नाम पर रखे गए थे जिनका उनमें प्रतिनिधित्व था। तथापि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से सरकार की यह नीति रही है कि किसी वर्ग, समुदाय, धर्म या क्षेत्र के नाम पर कोई नई रेजिमेंट खड़ी न की जाए। सभी नागरिक चाहे वे किसी भी वर्ग, पंथ, क्षेत्र के हों या कोई भी भाषा बोलते हों, वे भारतीय सेना में भर्ती के लिए पात्र हैं बशर्ते कि वे चयन के लिए भर्ती संबंधी मानदण्ड पूरे करते हों।